

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 अप्रैल 2024 — चैत्र 15, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 अप्रैल 2024

क्र. 3586/डी. 33/21-अ/प्रारू./छ.ग./24. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-03-2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 4 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024.

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) में अग्रतर संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा।
- (2) यह उस तारीख की प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

- धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में:-

- (1) खंड (80) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(80क) “ऑनलाइन गेम खेलना” से अभिप्रेत है इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना और इसमें ऑनलाइन धन संबंधी गेम खेलना भी शामिल है;

(80ख) “ऑनलाइन धन संबंधी गेम खेलना” से अभिप्रेत है ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन सहित गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया में, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, का संदाय

या जमा करता है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;"

(2) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से अभिप्रेत है—

(i)	दांव लगाने;
(ii)	कैसिनो;
(iii)	घूतफ्रीड़ा;
(iv)	घुड़दौड़;
(v)	लाटरी; या
(vi)	ऑनलाइन धन संबंधी गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा;"

(3) खंड (105) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या प्रबंध करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जो ऐसे प्रदाय के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, को ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदायकर्ता समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों, उसके द्वारा या उसके माध्यम से प्रदाय किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों के प्रदाय के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसके निर्वर्तन

के लिये रखे जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे प्रदायकर्ता को लागू होंगे, मानों वह ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदाय करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी प्रदायकर्ता हो।”

(4) खंड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(117क) “आभासी डिजिटल आस्ति” का वही अर्थ होगा, जैसा कि आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (47क) में उसके लिये समनुदेशित है;”

धारा 10 का
संशोधन.

3.

मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(1) उपधारा (2) के खंड (घ) में, शब्द “माल या” का लोप किया जाये; और

(2) उपधारा (2क) के खंड (ग) में, शब्द “माल या” का लोप किया जाये।

धारा 16 का
संशोधन.

4.

मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में,—

(1) द्वितीय परन्तुक में, वाक्यांश “उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा” के स्थान पर, वाक्यांश “धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(2) तृतीय परन्तुक में, वाक्यांश “उसके द्वारा किए गए संदाय” के स्थान पर, वाक्यांश “उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 17 का
संशोधन.

5.

मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(1) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्ति “छूट—प्राप्त प्रदाय का मूल्य” में,

(i) अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्य-कलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और

(ii) अनुसूची 3 के पैरा 8 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसे कार्य-कलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित की जाए,

के सिवाय अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।”

(2) उपधारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(च क) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;”

6. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

धारा 23 का संशोधन.

“(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी तत्प्राप्तिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्याधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जाए, उन व्यक्तियों, जिन्हें इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दिया जा सकता हो, की श्रेणी विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

टीप- उपरोक्त उपधारा (2) को 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त किया गया समझा जायेगा।”

7. मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (xi) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

धारा 24 का संशोधन.

“(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत से बाहर के स्थान से भारत के व्यक्तियों को ऑनलाईन

सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवायें,
प्रदान करता हो;

(xi) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धन संबंधी गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और”

धारा 30 का
संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में,—

(i) वाक्यांश “तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से” के स्थान पर, वाक्यांश “ऐसे तरीके एवं ऐसे समय और निर्बंधनों एवं शर्तों, जैसा कि विहित किया जाये, के अध्यक्षीन रहते हुये, ऐसे अधिकारी को” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) परंतुक का लोप किया जाये।

धारा 37 का
संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों की प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी, अनुज्ञात कर सकेगी।”

धारा 39 का
संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए, विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के

पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी, अनुज्ञात कर सकेगी।”

11. मूल अधिनियम की धारा 44 में,—

धारा 44 का संशोधन.

(1) वाक्यांश “किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न” के पूर्व, अंक एवं चिह्न “(1)” अंतःस्थापित किया जाये; और

(2) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

“(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये, उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी, अनुज्ञात कर सकेगी।”

12. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

धारा 52 का संशोधन.

“(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने

की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के लिये, उक्त विवरणों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी, अनुज्ञात कर सकेगी।”

- | | | |
|--------------------|-----|--|
| धारा 54 का संशोधन. | 13. | मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में, वाक्यांश “जिसके अंतर्गत अनंतिम स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,” का लोप किया जाये। |
| धारा 56 का संशोधन. | 14. | मूल अधिनियम की धारा 56 में, वाक्यांश “आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक” के स्थान पर, वाक्यांश “आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक हुए विलम्ब की अवधि के लिए, ऐसी रीति से एवं ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के अध्वधीन संगणना करते हुए, जैसा कि विहित किया जाये,” प्रतिस्थापित किया जाये। |
| धारा 62 का संशोधन. | 15. | <p>मूल अधिनियम की धारा 62,—</p> <p>(1) उपधारा (2) में, शब्द “तीस दिन” के स्थान पर, शब्द “साठ दिन” प्रतिस्थापित किया जाये; और</p> <p>(2) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-</p> |

“परंतु जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामिली के साठ दिनों के अन्दर वैध विवरणी दाखिल करने में विफल रहता हो, वहाँ वह उक्त विवरणी, उक्त निर्धारण आदेश की तामिली के साठ दिनों के पश्चात्, अगले साठ दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे विलम्ब की अवधि हेतु एक सौ रुपये प्रतिदिन के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क का भुगतान करते हुए, दाखिल कर सकेगा एवं यदि वह इस विस्तारित अवधि के भीतर वैध विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश को

वापस लिया जाना माना जाएगा, किन्तु अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान करने अथवा अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क का भुगतान करने का दायित्व निरन्तर बना रहेगा।”

16. मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—
 धारा 109 का संशोधन.
 “109. अपीलीय अधिकरणों और उनकी पीठों का गठन.— इस अध्याय के प्रावधानों के अध्वधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 12 सन् 2017) के अंतर्गत गठित “माल और सेवा कर अधिकरण”, इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये अपीलीय अधिकरण होगा।”
17. मूल अधिनियम की धारा 110 एवं 114 का लोप किया जाये।
 धारा 110 एवं 114 का लोप.
18. मूल अधिनियम की धारा 117 में,—
 धारा 117 का संशोधन.
 (1) उपधारा (1) में, वाक्यांश “राज्य पीठ या अपीलीय अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों” के स्थान पर, वाक्यांश “अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठों” प्रतिस्थापित किया जाये।
 (2) उपधारा (5) के खंड (क) एवं (ख) में, वाक्यांश “राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ” के स्थान पर, शब्द “राज्य पीठों” प्रतिस्थापित किया जाये।
19. मूल अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खंड (क) में, वाक्यांश “राष्ट्रीय पीठ या अपीलीय अधिकरण की प्रांतीय पीठों” के स्थान पर, वाक्यांश “अपीलीय अधिकरण की प्रधान पीठ” प्रतिस्थापित की जाये।
 धारा 118 का संशोधन.
20. मूल अधिनियम की धारा 119 में,—
 धारा 119 का संशोधन.
 (1) वाक्यांश “राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों” के स्थान पर, शब्द “प्रधान पीठ” प्रतिस्थापित की जाये।
 (2) वाक्यांश “राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों” के स्थान पर, शब्द “राज्य

पीठों" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 122 का
संशोधन.

21.

मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाये, अर्थात् :-

“(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो -

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है;

(ii) इसके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है, के द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के सही ब्यौरे, धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में, प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

तो वह दस हजार रुपये या अंतर्वर्तित कर की रकम, यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।”

धारा 132 का
संशोधन.

22.

मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,-

(1) खंड (छ), (ज) और (ट) का लोप किया जाये;

(2) खंड (ठ) में, शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर “खंड (क) से खंड (ट)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर “खंड (क) से (च) और खंड (ज) तथा (झ)” प्रतिस्थापित किया जाये;

(3) खंड (iii) में, वाक्यांश “जहां कर अपवंचन” के स्थान पर, वाक्यांश “खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन” प्रतिस्थापित किया जाये;

(4) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (छ) या खंड (ज)" का लोप किया जाएगा।

23. मूल अधिनियम की धारा 138 में,—

धारा 138 का
संशोधन.

(1) उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,
अर्थात् :—

"(क) कोई व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज), खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है,"

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाये;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है,"

(iv) खंड (ङ) का लोप किया जाये;

(2) उपधारा (2) में, वाक्यांश "रकम अंतर्वलित कर के दस हजार रुपये या पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हों, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये से अन्यून या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिकतम हो," के स्थान पर, वाक्यांश "न्यूनतम रकम, अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून और अधिकतम रकम, अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक" प्रतिस्थापित किया जाये।

24. मूल अधिनियम की धारा 138 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

नवीन धारा
138क का

अंतःस्थापन.

“138क. संक्रमणकालीन उपबंध.— इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, घूत क्रीड़ा, घुडदौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।”

नवीन धारा

25.

मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

158क का

अंतःस्थापन.

“158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना—

(1) धारा 133, 152 और 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए तथा परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाये, सामान्य पोर्टल द्वारा, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या 44 के अधीन दाखिल की गई विवरणी में प्रस्तुत की गई विशिष्टियाँ;

(ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ;

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्यौरों के साझा करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि विहित किया जाये,

निम्नलिखित की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में, पूर्तिकर्ता; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) एवं (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में, प्राप्तिकर्ता, केवल जहां ऐसे ब्यौरों में प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी शामिल हो।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत भूति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।”

28.

मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,—

अनुसूची 3 का
संशोधन.

(1) पैरा 6 में, वाक्यांश “लाटरी, दांव और जुआ” के स्थान पर, वाक्यांश “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों” प्रतिस्थापित किया जाये; और

(2) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“टीप— (1) उपरोक्त पैरा 7, 8 तथा स्पष्टीकरण 2 को 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त किया गया समझा जायेगा।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है, किन्तु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता, यदि उपरोक्त टीप के उपबंध, सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

अटल नगर, दिनांक 4 अप्रैल 2024

क्र. 3586/डी. 33/21-अ/प्रा.रू./छ.ग./24. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 04-04-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 4 of 2024)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2024.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows: -

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act),-

- (1) after clause (80), the following shall be inserted, namely:—

“(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;”

- (2) after clause (102), the following shall be inserted, namely:—

“(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of—

(i)	betting;
(ii)	casinos;
(iii)	gambling;
(iv)	horse racing;
(v)	lottery; or
(vi)	online money gaming;”

- (3) after clause (105), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid

or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"

- (4) after clause (117), the following shall be inserted, namely:—

“(117A)"virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (No.43 of 1961);”

3. In Section 10 of the Principal Act,—

**Amendment of
Section 10.**

- (1) in clause (d) of sub-section (2), the words "goods or" shall be omitted; and
- (2) in clause (c) of sub-section (2A), the words "goods or" shall be omitted.

4. In sub-section (2) of Section 16 of the Principal Act, —

**Amendment of
Section 16.**

- (1) in the second proviso, for the protasis "added to his

output tax liability, along with interest thereon in such manner as may be prescribed", the protasis "paid by him along with interest payable under Section 50 in such manner as may be prescribed" shall be substituted;

- (2) in the third proviso, for the protasis "made by him", the protasis "made by him to the supplier" shall be substituted.

**Amendment of
Section 17.**

5. In Section 17 of the Principal Act,—

- (1) for Explanation of subsection (3), the following shall be substituted, namely:—

“Explanation- For the purposes of this subsection, the expression “value of exempt supply” shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III,

except,—

- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the Schedule III; and
- (ii) the value of such activities or

transactions as may be prescribed in clause (a) of paragraph 8 of the Schedule III."

- (2) after clause (f) of sub-section (5), the following shall be inserted, namely:—

"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to Section 135 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013);"

6. For sub-section (2) of Section 23 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**Amendment of
Section 23.**

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of Section 22 or Section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify

the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.

Note- Above sub-section (2) shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of July, 2017."

**Amendment of
Section 24.**

7. For clause (xi) of Section 24 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(xi) Every person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person;

(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and"

**Amendment of
Section 30.**

8. In sub-section (1) of Section 30 of the Principal Act,—

(1) for the protasis "the prescribed manner within thirty days", the protasis "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted;

(2) the proviso shall be omitted.

9. After sub-section (4) of Section 37 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:—

**Amendment of
Section 37.**

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the period of three years from the due date of furnishing the said details."

10. After sub-section (10) of Section 39 of the Principal Act, the following shall be added, namely:—

**Amendment of
Section 39.**

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period

after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the period of three years from the due date of furnishing the said return."

**Amendment of
Section 44.**

11. In Section 44 of the Principal Act,-

- (1) before the protasis "Every registered person", the figure and symbol "(1)" shall be inserted; and
- (2) after sub-section (1) the following shall be inserted, namely:—

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

12. After sub-section (14) of Section 52 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:—

**Amendment of
Section 52.**

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be

specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."

**Amendment of
Section 54.**

13.

In sub-section (6) of Section 54 of the Principal Act, the protasis "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.

**Amendment of
Section 56.**

14.

In Section 56 of the Principal Act, for the protasis "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the protasis "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application under the said sub-section till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.

**Amendment of
Section 62.**

15.

In Section 62 of the Principal Act,-

(1) in sub-section (2), for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted; and

(2) after sub-section (2), the following shall be added, namely:-

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of Section 50 or to pay late fee under Section 47 shall continue."

16. For Section 109 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:—

**Amendment of
Section 109.**

"109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches Thereof.- subject to provisions of this Chapter, the "Goods and Services Tax Tribunal"

constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No.12 of 2017) shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under This Act.”

**Omission of
Section 110 and
114.**

17. Section 110 and 114 of the Principal Act will be omitted.

**Amendment of
Section 117.**

18. In Section 117 of the Principal Act,—

(1) in sub-section (1), for the protasis “State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal”, the protasis “State Benches of the Appellate Tribunal” shall be substituted;

(2) in clause (a) and (b) of sub-section (5), for the protasis “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be substituted.

**Amendment of
Section 118.**

19. In clause (a) of sub-section (1) of Section 118 of the Principal Act, for the protasis “National Bench or Regional Benches of the Appellate Tribunal”, the protasis “Principal Bench of the Appellate Tribunal” shall be substituted.

20. In Section 119 of the Principal Act,— **Amendment of Section 119.**

- (1) for the protasis “National or Regional Benches”, the words “Principal Bench” shall be substituted;
- (2) for the protasis “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be substituted.

21. After sub-section (1A) of Section 122 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 122.**

“(1B)Any electronic commerce operator who—

- (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act;
- (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
- (iii) fails to furnish the correct details, in

the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52, of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."

**Amendment of
Section 132.**

22.

In sub-section (1) of Section 132 of the Principal Act,—

- (1) clause (g), (j) and (k) shall be omitted;
- (2) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;
- (3) in clause (iii), for the protasis "any other offence", the protasis "an offence specified in clause (b)," shall be substituted;

(4) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be omitted.

23. In Section 138 of the Principal Act,—

**Amendment of
Section 138.**

(1) in the first proviso of sub-section (1), —

(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

"(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;"

(ii) clause (b) shall be omitted;

(iii) for clause (c), the following shall be substituted, namely:—

"(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;"

(iv) clause (e) shall be omitted;

(2) in sub-section (2), for the protasis "ten thousand rupees or fifty percent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty percent of the tax, whichever is higher", the protasis "twenty-five percent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred percent of the tax involved" shall be substituted.

**Insertion of new
Section 138A.**

24.

After Section 138 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"138A. Transitory Provision.-

The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

**Insertion of new
Section 158A.**

25.

After Section 158 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:—

**"158A. Consent based sharing
of information**

furnished by taxable person.-

(1) Notwithstanding anything contained in Section 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

(a) particulars furnished in the application for registration under Section 25 or in the return filed under Section 39 or 44;

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation

of invoice, the details of outward supplies furnished under Section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under Section 68;

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity

information of
the recipient,

in such form and
manner as may be
prescribed.

- (3) Notwithstanding
anything contained
in any law for the
time being in force,
no action shall lie
against the
Government or the
common portal with
respect to any
liability arising
consequent to
information shared
under this section
and there shall be
no impact on the
liability to pay tax
on the relevant
supply or as per the
relevant return."

26. In Schedule III of the Principal
Act,-

**Amendment of
Schedule-III.**

- (1) in paragraph 6, for the
protasis "lottery, betting
and gambling" the protasis
"specified actionable
claims" shall be
substituted; and
- (2) after explanation 2, the
following shall be added,
namely:-

"Note-(1) paragraph 7, 8
and explanation 2

above shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had subsection (1) been in force at all material times.”